भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 524**

**03.02.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**पीएम ई-ड्राइव योजना**

524. **श्री मनीष जायसवालः**

**श्री विजय कुमार दूबेः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-ड्राइव योजना ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार गति दी है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिसम्बर, 2025 तक इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

**(क) एवं (ख)** : पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के अंगीकरण में तीव्रता आई है। इसके तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया (ई-रिक्शा, ई-कार्ट्स और एल5 श्रेणी), ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक जैसे कई ईवी खंडों के लिए लक्षित मांग प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शुरुआती लागत कम हो गई है। इस स्कीम के तहत, उपभोक्ताओं (खरीदारों/एंड यूज़र्स) को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कीमत कम करने के लिए अग्रिम प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिसका भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को प्रतिपूर्ति की जाती है।

यह स्कीम 28 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान करती है। 27 जनवरी 2026 तक, इस स्कीम के तहत कुल 22.12 लाख ईवी बेची जा चुकी हैं, जिनमें 19.19 लाख ई-दुपहिया और 2.93 लाख ई-तिपहिया शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, इस स्कीम में 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से, 13,800 ई-बसें दो चरणों में, चार मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले सात शहरों, यानी बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत में तैनाती के लिए आबंटित की गई हैं। चरण I में दी गई 10,900 ई-बसों के लिए सीईएसएल ने टेंडर पहले ही

पूरे कर लिए हैं, जबकि चरण-II में आवंटित की गई बाकी 2,900 ई-बसों के लिए टेंडर 09.01.2026 को जारी किए गए थे।

यह स्कीम ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और परीक्षण सुविधाओं के स्तरोन्नयन में भी मदद करती है। इस स्कीम के तहत पूरे भारत में ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इन उपायों से ईवी पारितंत्र सुदृढ़ हुआ है, उपभोक्ता का भरोसा बढ़ा है, और बड़े पैमाने पर स्वच्छ और संधारणीय परिवहन साधनों को अपनाने में मदद मिली है।

**(ग)** : 31 दिसंबर, 2025 तक, ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के खरीदारों को दिए गए मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के तौर पर कुल 1,703 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

*******